भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 360 का उत्तर

आंध्र प्रदेश में लंबित रेल परियोजनाएं

360. डॉ. बायरेड्डी शबरीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आंध्र प्रदेश में लंबित रेललाइन परियोजनाओं के संबंध में कोई आंकडें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम तक रेललाइन बिछाने के लिए व्यवहार्यता-अध्ययन पूरा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे बोर्ड ने श्रीशैलम तक रेल-संपर्क में सुधार के लिए कोई पहल की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या नांदयाल में मार्ग-दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

s.k

आंध्र प्रदेश में लंबित रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में डॉ. बायरेड्डी शबरी के अतारांकित प्रश्न सं. 360 के भाग (क) से (ज) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ज): रेल परियोजनाओं को राज्य वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत तथा निष्पादित किया जाता है क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली ₹73,743 करोड़ की लागत पर कुल 5,329 किलोमीटर लंबाई की कुल 41 रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं (17 नई लाइन और 24 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निष्पादन के चरण में हैं, जिनमें से 1006 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक लगभग ₹24,150 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली नई लाइन और दोहरीकरण परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेलवे-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता गया है।

2014 से, भारतीय रेल में निधि आवंटन और तद्नुरूप परियोजनाओं को चालू करने में काफी वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशत: स्थित अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए वार्षिक बजट आवंटन निम्नानुसार है:-

वर्ष	बजट परिव्यय	2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	₹ 886 करोड़/प्रति वर्ष	-
2023-24	₹8,406 करोड़	9 गुना से अधिक

s.k

आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशत: स्थित अवसंरचना परियोजनाओं को कमीशनिंग करने की स्थिति निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन की गई कुल लंबाई	कमीशन की गई औसत लंबाई	2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	363 किलोमीटर	72.6 किलोमीटर/प्रति वर्ष	-
2014-24	1,510 किलोमीटर	151 किलोमीटर/प्रति वर्ष	2 गुना से अधिक

हैदराबाद (तिम्मापुर)-श्रीशेलम (103.60 किलोमीटर) के बीच नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा किया गया था। बहरहाल, कम यातायात संभावना के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

भारतीय रेलों पर रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृत करना सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रेल अवसंरचानात्मक परियोजनाओं की लाभप्रदता, अंतिम छोर पर संपर्क, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, भीड़-भाड़/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, सामाजिक-आर्थिक पहलुओं आदि के आधार पर शुरू किया जाता है जो चालू परियोजनाओं की दायिताओं, निधि की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है।

नंदयाल चालू गुंटूर-गुंतकल (401 किमी) दोहरीकरण परियोजना का एक हिस्सा है, जिसकी लागत 3887.48 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान, 480 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। परियोजना की 401 कि.मी. लम्बाई में से 313 कि.मी. को कमीशन कर दिया गया है।

रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना/निष्पादन राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, उस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति,

जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना(ओं) के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य में, नांद्याल में विद्युतीकृत कार्य सहित बड़ी लाइनों को 100% विद्युतीकृत किया गया है।

*****

s.k